आदि, लेखा परीक्षण शुल्क, निदेशकों की फीस और भत्ते तथा प्रासंगिक खर्चे शामिल हैं। प्रशासनिक खर्चों में वृद्धि होने का मुख्य कारण यह है कि बढ़े हुए उत्पादन तथा वसूली के कारण और बीज गोदामों को किराए पर लिया गया है तथा लेखा-परीक्षण शुल्क और निदेशकों की फीस और भत्ते भी बढ़ गए हैं।

(ख) यह निगम मिट्टी की जांच करने के लिये किसानों को सस्ती दरों पर बीज सप्लाई नहीं करता है।

(ग) यह निगम किसानों के लिए उर्वरकों और कीटनाशी दवाओं की व्यवस्था नहीं करता है। यह राज्य सरकारों का काम है।

(घ) किसानों के लाभ के लिये खर्च करने का कोई भी प्रस्ताव इस निगम के विचाराधीन नहीं है। निगम बढ़िया किस्म के बीजों का उत्पादन और सप्लाई करता है। बढ़िया किस्म के बीजों के प्रयोग से किसानों का लाभ होता है।

tITHE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB SHINDE): (a)
The official year of the Corporation is from 1st June to 31st May. Administrative expenses incurred by the Corporation in the past three years were as under: —

Year	Amount
1970-71 . .	Rs. 16·70 lakhs
1971-72 . .	Rs. 17·73 lakhs
1972-73 . .	Rs. 22·94 lakhs

Accounts for the period from June, 1973 to October, 1973 have not yet been compiled.

These include rent for seed godowns, rates and taxes, audit fee, Directors' tee and allowances and contingencies. The main reason for increase in the administrative expenses is on account of more seed godowns having been taken on rent due to increased production and procurement and an increase in the audit fee and Directors' fee and allowances.

(c) The Corporation does not supply seeds to the farmers at concessional rates, for conducting soil study.

(c) The Corporation does not provide fertilizers and pesticides to the farmers which is the responsibility of the State Governments.

(d) No proposal for expenditures for the benefit of farmers is under the consideration of the Corporation The Corporation is engaged in the production and supply of high quality seeds and the farmers stand to benefit by using quality seeds.]

लाख के विकास के लिए संस्थान

1086. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार लाख के निर्यात के लिए लाख उत्पादन को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से लाख उद्योग का विकास करने हेतु एक समन्वित संस्थान बनाने का विचार रखती है ?

Institution for the development of lac

1086. SHRI J. P. YADAV: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state whether Government propose to set up an integrated institution for the development of lac with a view' to organising lac production for export purposes?]

†[ ] English translation.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : लाख उत्पादन की व्यवस्था राज्य सरकारें कर रही हैं। तथापि विकास कार्यक्रमों को नियोजित और समन्वित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय स्तर पर एक लाख विकास निदेशालय पहले से ही कार्य कर रहा है जिसका मुख्य कार्यालय रांची में है। इसके अलावा लाख के विकास, विपणन, व्यापार, मूल्यों आदि से संबंधित मामलों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिये एक भारतीय लाख विकास परिषद् का भी गठन किया गया है जिसमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, उत्पादकों, व्यापारियों आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं।

t[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB SHINDE): Lac production is being organised by the State Governments. However, with a view to planning and coordinating the development programmes a Directorate of Lac Development with its Headquarters at Ranchi is already .functioning at the Central level. Besides, an Indian Lac Development Council comprising the representatives of Central and State Governments, growers, traders etc. has also been set up to advise the Government of India on matters relating to the development, marketing, trading, prices etc.]

लाख का उत्पादन और निर्यात

1887. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि देश में उत्पादित लाख का अधिकांश भाग निर्यात किया जाता है और क्या उसके उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार यह काम औद्योगिक विकास मंत्रालय को सौंपने का विचार रखती है?

tl Production and export of Lac

1087. SHRI J. P. YADAV: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state whether it is a fact that most of the lac produced in the country is exported and whether with a view to augment its production, Government propose to hand over this work to the Ministry of Industrial Development?]

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : जी, हां। देश में उत्पादित लाख का अधिकांश भाग निर्यात किया जाता है। यह कार्य औद्योगिक विकास मंत्रालय को स्थानान्तरण करने संबंधी प्रस्ताव की इस मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है।

t[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB SHINDE): Yes, Sir. Most of the lac produced in the country is exported. This Ministry is not aware of any proposal for the transfer of this work to the Ministry of Industrial Development.]

Taking over of Konkan coastal shipping services

1088. MISS SAROJ PURUSHOT-TAM KHAPARDE: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the Maharashtra Government have recommended to the Central Government to take over the Konkan Coastal Shipping Services run by the Chowgule Steamships Ltd.; and

(b) the action taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI KAMALA-PATI TRIPATHI): (a) Yes, Sir.

†[ ] English translation.